

# ब्यूज टुडे

## निजी क्षेत्रक द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया गया

हाल ही में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह 'फायरफ्लाई' लॉन्च किया।

- ▶ फायरफ्लाई उपग्रह समूह के पहले तीन उपग्रहों को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। उन्हें कैलिफोर्निया के वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया है।
- ▶ फायरफ्लाई, पिक्सल का प्रमुख हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (HSI) उपग्रह समूह है। इसमें अब तक के उच्चतम-रिज़ॉल्यूशन वाले 6 वाणिज्यिक हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं।

हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (HSI) उपग्रहों के बारे में

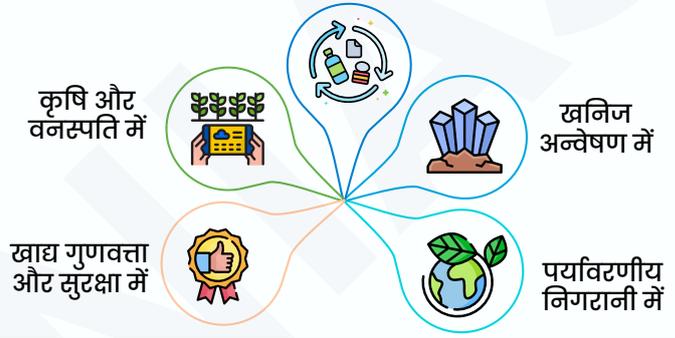
- ▶ HSI के तहत प्रत्येक पिक्सल को केवल प्राथमिक रंग (लाल, हरा व नीला) प्रदान करने की बजाय प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। इससे प्रभावी रूप से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंटिंग करना संभव हो जाता है।
- ▶ HSI से हमें अधिक जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य उपग्रह अंतरिक्ष से वन की पहचान कर सकता है, वहीं HSI विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच अंतर कर सकता है। साथ ही, प्रत्येक वृक्ष के स्वास्थ्य का निर्धारण भी कर सकता है।

उपग्रह समूह (Satellite Constellation) के बारे में

- ▶ यह समान उद्देश्य और साझा नियंत्रण वाले समरूप कृत्रिम उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है। इसे एक प्रणाली के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - ⊕ ये पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों के साथ कनेक्ट रहते हैं और कभी-कभी एक-दूसरे के कार्यों को पूरा करने के लिए आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं।
- ▶ 2,146 सक्रिय उपग्रहों के साथ स्टारलिक सबसे बड़ा उपग्रह समूह है।
- ▶ प्रकार: ये कक्षा की ऊंचाई के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं-
  - ⊕ भू-स्थिर कक्षा (GEO): यह कक्षा 36,000 कि.मी. की ऊंचाई पर होती है। उपग्रह इस कक्षा में इस तरह से पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं कि उनकी गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान रहती है।
  - ⊕ मध्य भू-कक्षा (MEO): यह कक्षा 5,000 से 20,000 कि.मी. की ऊंचाई पर होती है। यह कक्षा मुख्य रूप से नेविगेशन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।
  - ⊕ निम्न भू-कक्षा (LEO): यह कक्षा 500 से 1,200 कि.मी. की ऊंचाई पर होती है। यह कक्षा अनुसंधान, दूरसंचार और भू-पर्यवेक्षण जैसे कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।

### हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के विविध उपयोग

अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण में



## प्रधान मंत्री ने तीन अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधान मंत्री ने तीन अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों (INS सूरत, INS नीलगिरि और INS वाघशीर) राष्ट्र को समर्पित किया।

यह पहली बार है, जब स्वदेशी रूप से विकसित एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। यह नौसेना के लिए स्वदेशीकरण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक लीडर बनने के भारत के विज्ञान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तीन अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों के बारे में

- ▶ INS सूरत: यह P15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम पोत है।
- ▶ INS नीलगिरि: इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है। यह P17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला पोत है।
- ▶ INS वाघशीर: यह मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह P75 स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट के तहत विकसित की गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है।
  - ⊕ यह फ्रेंच स्कॉर्पिन-क्लास डिज़ाइन पर आधारित कलवरी-क्लास की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है।

भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के प्रयास

- ▶ नीतियां
  - ⊕ भारतीय नौसेना का मेरीटाइम कैपबिलिटी पर्स्पेक्टिव प्लान (MCP): इसका उद्देश्य 2027 तक 200 जहाजों का बेड़ा तैयार करना है। इसका विज़न 'खरीदार नौसेना की जगह विनिर्माता नौसेना' का लक्ष्य हासिल करना है।
  - ⊕ भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (INIP) 2015-2030: इस योजना के तहत जहाजों के विनिर्माण कार्य में संलग्न MSMEs सहित घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- ▶ मेक इन इंडिया पहल में भारतीय नौसेना को शामिल करना: पिछले दशक में नौसेना में शामिल 40 नौसैनिक जहाजों में से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किया गया था।
  - ⊕ उदाहरण के लिए INS विक्रान्त (विमान वाहक), INS अरिहंत और INS अरिघाट (परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी)।
- ▶ अनुसंधान एवं विकास पहल: अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (समुद्रयान परियोजना); हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी तथा माइंस का पता लगाने जैसे उच्च जोखिम वाले परिवेश के लिए स्वायत्त प्रणालियों का विकास आदि।

### नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के रणनीतिक लाभ

क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास (सागर/ SAGAR) नीति

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में स्थापित करना।

व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना  
व्यापार से संबंधित आपूर्ति मार्गों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना



आत्मनिर्भरता

रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना

## ‘ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025’ रिपोर्ट जारी की गई

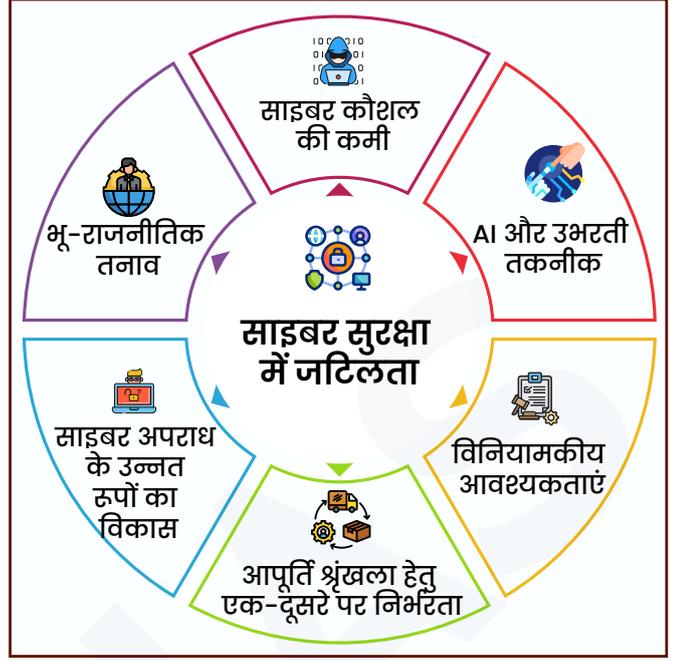
यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने एक्सचेंजर के साथ मिलकर जारी की है। इस रिपोर्ट में साइबर परिवेश की बढ़ती जटिलता (इन्फोग्राफिक देखें) तथा संगठनों और राष्ट्रों पर इसके व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साइबर अपराध ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बाधित किया है। इससे 2023 में 12.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।

साइबर सुरक्षा संबंधी जटिलताओं में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक-

- आपूर्ति श्रृंखला की सुभेद्यताएं: आपूर्ति श्रृंखलाओं की बढ़ती जटिलता और सीमित निगरानी के कारण जोखिम उत्पन्न होते हैं। साथ ही, थर्ड-पार्टी द्वारा इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर संबंधी खामियां भी हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को साइबर हमले के प्रति सुभेद्य बना देती हैं।
- भू-राजनीतिक तनाव: विभिन्न देशों के बीच संघर्ष एडवांस साइबर रणनीतियों को बढ़ावा देते हैं। इससे ऊर्जा और दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमला होने का खतरा बढ़ जाता है।
- AI-जनित खतरें: जनरेटिव AI लागत-प्रभावी व स्केलेबल मैलवेयर की अपलोडिंग और उन्नत बहुभाषी सोशल इंजीनियरिंग हमलों को सक्षम बनाता है।
  - बहुभाषी सोशल इंजीनियरिंग हमला: कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ हेर-फेर करना।
- साइबर संबंधी कौशलों की कमी: साइबर सुरक्षा हेतु आवश्यक कौशल प्रसार में अनुमानतः 8% का अंतर है। इसके परिणामस्वरूप, लगभग दो-तिहाई संगठन प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव के कारण साइबर खतरों से स्वयं को पर्याप्त रूप से बचाने में असमर्थ हैं।
- साइबर अपराध और संगठित अपराध का आपस में मिला होना: बढ़ती साइबर धोखाधड़ी ने हिंसक गतिविधियों में शामिल संगठित आपराधिक समूहों को साइबर क्षेत्र में खींच लिया है। इससे साइबर अपराध का पैमाना और सामाजिक प्रभाव काफी बढ़ गया है।
- जलवायु से जुड़े साइबर जोखिम: विकसित हो रही आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों पर निर्भरता के कारण ऊर्जा ग्रिडों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
- क्वांटम से संबंधित सुभेद्यताएं: क्वांटम कंप्यूटिंग डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पब्लिक-की एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता रखती है।

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि साइबर चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। साथ ही, साइबर सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में पहचानना होगा। नेताओं को उभरते खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा को एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखना चाहिए।



## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्ट-अप इंडिया पहल के 9 वर्ष पूरे हुए

स्टार्ट-अप इंडिया पहल को 2016 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था।

स्टार्ट-अप इंडिया पहल की मुख्य विशेषताएं

- उद्देश्य: भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- इस पहल की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:
  - कारोबार करने की सुगमता: इसके तहत सरलीकृत अनुपालन, स्व-प्रमाणन और सिंगल विंडो क्लियरेंस को बढ़ावा दिया गया है।
  - कर संबंधी लाभ: इसमें लगातार तीन वित्त वर्षों के लिए कर संबंधी छूट का प्रावधान किया गया है।
  - वित्त-पोषण संबंधी सहायता: स्टार्ट-अप के लिए प्रारंभिक चरण के वित्त-पोषण हेतु मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप (FFS) का निर्माण किया गया है।
  - क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां: इसमें जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए नीतियां शामिल हैं।
- स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं
  - स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS): यह चार साल की योजना है। यह स्टार्ट-अप को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, वाणिज्यीकरण आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है।
  - स्टार्ट-अप के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS): यह योजना पाल स्टार्टअप को दिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करती है।
  - फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप (FFS) योजना: इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्ट-अप की घरेलू पूंजी तक पहुंच को बढ़ाना है।

इसके तहत हासिल प्रमुख उपलब्धियां

- स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि: DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 2016 की 500 से बढ़कर वर्तमान 2025 में 1.59 लाख हो गई है।
- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: भारत 100 से अधिक यूनिवर्सिटी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है।
- रोजगार सृजन: इसके तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है।
- महिला सशक्तीकरण: 73,151 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में कम-से-कम एक महिला निदेशक है।

स्टार्ट-अप इंडिया के तहत अन्य पहलें

- भारत स्टार्ट-अप नॉलेज एक्सचेंज रजिस्ट्री (भास्कर) प्लेटफॉर्म: इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। यह उद्यमियों, निवेशकों, सलाहकारों, नीति निर्माताओं और अन्य स्टार्ट-अप इकोसिस्टम हितधारकों को आपस में जोड़ता है।
- MAARG मॉडरनिजेशन प्लेटफॉर्म: यह प्लेटफॉर्म सलाहकारों और स्टार्ट-अप के बीच सही मिलान करने में मदद करता है, ताकि प्रभावी मार्गदर्शन व समर्थन प्राप्त हो सके।
- स्टार्ट-अप इंडिया हब पोर्टल: यह एक व्यापक डिजिटल मंच है, जो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों को सेवाएं प्रदान करता है।
- राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग प्रेमवर्क: यह पहल क्षेत्रीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य स्तर पर स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करती है।

## इजरायल और हमास गाजा युद्धविराम एवं बंधक रिहाई समझौते पर सहमत हुए

हमास और इजरायल के बीच 15 महीने तक चले संघर्ष के बाद युद्धविराम समझौता हुआ है।

वर्तमान संघर्ष की पृष्ठभूमि

- 7 अक्टूबर, 2023 को हमास ने "ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म" के तहत इजरायल पर एक बड़ा हमला किया था। यह हमला योम किप्पर युद्ध (1973) की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था।
- इसकी प्रतिक्रिया में इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध और उसके बाद गाजा में सैन्य अभियानों की घोषणा कर दी थी।

ऐतिहासिक संदर्भ

हमास और इजरायल के बीच मौजूदा संघर्ष की जड़ें फिलिस्तीनी क्षेत्र के विभाजन और अरबों द्वारा इजरायल को मान्यता नहीं देने से जुड़ी हुई हैं:

फिलिस्तीन का विभाजन

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन चले गए थे और अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे थे।
- 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अरबों और यहूदियों के बीच विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके कारण अरब और इजरायल के बीच 4 बड़े युद्ध हुए:



- यहूदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके 1948 में इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
- अरबों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई युद्ध हुए।

कैप डेविड समझौता (1978) और इजरायल को मान्यता

- वर्ष 1973 का योम किप्पर या रमजान युद्ध चौथा अरब-इजरायल युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ इजरायल था तो दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देश थे।
- इस युद्ध के परिणामस्वरूप 1978 में कैप डेविड समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पहली बार किसी अरब देश ने इजरायल को एक 'राज्य' के रूप में मान्यता दी। समझौते के तहत इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस लौटा दिया।

1993 का ओस्लो शांति समझौता और हमास द्वारा इजरायल को मान्यता देने का विरोध

- यह समझौता फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) और इजरायल के बीच हुआ था। इसके तहत PLO ने औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता दी थी तथा इजरायल ने फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक में सीमित स्वशासन की अनुमति दी थी। हालांकि, हमास, ओस्लो शांति समझौते (1993) का हिंसक तरीके से विरोध करता रहा है।
- PLO का गठन 1964 में किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र में एक गैर-सदस्य देश 'फिलिस्तीन' के नाम से फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है।
- हमास एक उग्रवादी संगठन है। यह राजनीतिक रूप से गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। यह समूह इजरायल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है।

## मैकिन्से ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और जनसंख्या में कमी पर एक रिपोर्ट जारी की

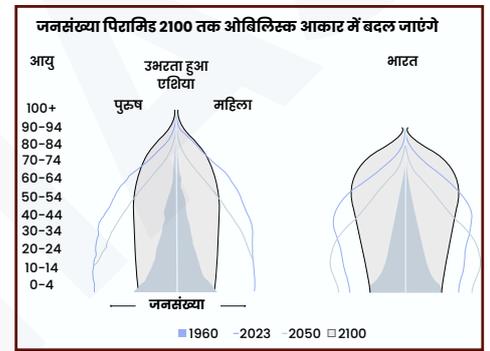
मैकिन्से की रिपोर्ट 'निर्भरता और जनसंख्या में कमी? एक नई जनसांख्यिकी वास्तविकता के परिणामों से सामना' शीर्षक से जारी की गई है।

- इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकी बदलाव की पहली लहर (First wave) और जनसांख्यिकी बदलाव की बाद की लहर (Later wave) की गतिशीलता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।
- जनसांख्यिकी बदलाव की पहली लहर विकसित देशों में देखी जा रही है, जबकि बाद की लहर विकासशील देशों में देखी जाएगी।

जनसांख्यिकी बदलाव (Demographic Transition) पर एक नजर

- जनसंख्या में कमी (Depopulation): विश्व की दो-तिहाई आबादी ऐसे देशों में रहती है, जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर (Replacement rate) से कम है। प्रति परिवार औसतन 2.1 बच्चों को प्रजनन की प्रतिस्थापन दर माना जाता है।
- आबादी समूह में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने और युवाओं की संख्या घटने के कारण आयु संरचना पिरामिड से ओबिलिस्क (संकरा स्तंभ) आकार में बदल रही है।
- संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 2100 तक, कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या 20%-50% तक कम हो जाएगी।

समर्थन अनुपात (Support Ratios) में गिरावट: रिपोर्ट के अनुसार 'समर्थन अनुपात में गिरावट आ रही है। इसके वर्तमान में 6.5 से कम होकर 2050 तक 3.9 हो जाने का अनुमान है।



समर्थन अनुपात

से तात्पर्य 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या की तुलना में 15-64 वर्ष (कामकाजी आयु) आयु वर्ग के लोगों की संख्या के अनुपात से है।

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं और चीन में, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुल उपभोग एवं उनकी आय के बीच का अंतर 1.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। इस वजह से इन देशों में श्रम आय का 50% सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए आवंटित करना पड़ सकता है।

भारत का घटता जनसांख्यिकीय लाभांश

- भारत के समक्ष जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए 33 वर्ष ही बचे हैं। इसका अर्थ है कि 2050 तक ही वह इसका लाभ उठा सकता है, क्योंकि इसके बाद भारत विकसित देशों के 'समर्थन अनुपात' स्तर तक पहुंच जाएगा।
- जनसांख्यिकीय लाभांश ने भारत की प्रति व्यक्ति सकल-घरेलू उत्पाद संवृद्धि में प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत अंक जोड़े हैं। हालांकि, 2050 तक यह योगदान घटकर प्रति वर्ष केवल 0.2% अंक रह जाएगा।

## अन्य सुर्खियां



### संयुक्त राज्य अमेरिका एंटीटी लिस्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधित कंपनियों की सूची वाली अपनी 'एंटीटी लिस्ट' से तीन भारतीय संस्थाओं को हटा दिया है।

- ये भारतीय संस्थाएं हैं- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL)।
- यह कदम 2008 में हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते को नया जीवन दे सकता है। अमेरिकी 'एंटीटी लिस्ट' के बारे में
- इसमें कुछ विदेशी व्यक्ति, व्यवसाय, अनुसंधान संस्थान, सरकारी संगठन आदि सूचीबद्ध हैं।
- इस सूची में शामिल एंटीटी को कुछ निर्दिष्ट सामग्रियों के व्यापार के लिए विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है।
- यहां लाइसेंस का अर्थ यह है कि जिन सामग्रियों का व्यापार किया जाएगा वे सामग्रियां आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) कार्यक्रम आदि के उपयोग में नहीं आएंगी।



### सियाचिन ग्लेशियर

रिलायंस जियो ने सियाचिन ग्लेशियर में 4जी और 5जी सेवाएं शुरू की।

सियाचिन ग्लेशियर के बारे में

- यह एक पीडमोंट प्रकार का ग्लेशियर है।
- यह ग्लेशियर काराकोरम रेंज (पश्चिम में साल्तोरो रिज और पूर्व में मुख्य काराकोरम रेंज के बीच) में स्थित है।
- यह ग्लेशियर इंदिरा कोल वेस्ट के पास है और मध्य एशिया व भारतीय उपमहाद्वीप के बीच सीमा बनाता है।
- यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर-ध्रुवीय ग्लेशियर है।
- पहला स्थान ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर का है।
- यह ग्लेशियर नुब्रा नदी का जल स्रोत है। नुब्रा नदी स्योक नदी की सहायक नदी है। स्योक नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है।
- इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
- 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।



### शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य

केंद्र सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के रूप में नामित किया है।

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- अवस्थिति: यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की मध्य ऊंचाई वाली श्रृंखला पर स्थित है।
- अभयारण्य का नाम देवी शिकारी देवी के नाम पर रखा गया है। अभयारण्य में देवी को समर्पित एक मंदिर भी है।
- जलनिकाय: जूनी खुद। यह ब्यास नदी की एक सहायक नदी है।
- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- वनस्पति: अल्पाइन चारागाह और शीतोष्ण पर्णपाती वन।
- जीव-जंतु: एशियाई काला भालू, तेंदुआ, बार्किंग डियर, विशाल उड़ने वाली गिलहरी आदि।



### कंपाला घोषणा-पत्र

पोस्ट-मालाबो कम्प्रेहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CAADP) पर अफ्रीकी संघ (EU) का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

- 10-वर्षीय CAADP रणनीति और कार्य योजना; तथा अफ्रीका में लोचशील एवं टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण पर कंपाला CAADP घोषणा-पत्र अपनाया गया है।

कंपाला घोषणा-पत्र के बारे में

- कंपाला घोषणा-पत्र मालाबो घोषणा-पत्र की अनुवर्ती है। मालाबो घोषणा-पत्र को 2014 अपनाया गया था। मालाबो घोषणा-पत्र साझा समृद्धि और बेहतर आजीविका के लिए त्वरित कृषि विकास एवं परिवर्तन पर आधारित था।
- इसकी कार्यान्वयन अवधि 2026-2035 होगी।
- इसमें छह प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका उद्देश्य अफ्रीका में कृषि-खाद्य प्रणाली को बदलना और उसे मजबूत करना है।



### ब्लू घोस्ट और रेजिलिएंस

हाल ही में, स्पेसएक्स फाल्कन-9 प्रक्षेपण यान ने अमेरिकी फायरफ्लाई एयरोस्पेस के ब्लू घोस्ट मिशन 1 और जापान की आईस्पेस कंपनी के रेजिलिएंस लूनर लैंडर को लॉन्च किया है।

ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में

- यह नासा की वाणिज्यिक 'लूनर पेलोड सेवा (CLPS)' पहल के तहत चंद्रमा की सतह पर 10 साइंस-टेक उपकरण पहुंचाएगा।
- यह चंद्रमा की सतह पर पहली बार कई अध्ययन करेगा। इनमें रेगोलिथ सैंपल संग्रह, वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्षमता, विकिरण सहनशील कंप्यूटिंग का परीक्षण आदि शामिल हैं।
- साथ ही, यह चंद्रमा पर धूल की मात्रा को कम करने तथा इससे उपकरणों और अंतरिक्ष यानों को होने वाले नुकसान को रोकने की प्रक्रिया का भी अध्ययन करेगा।

रेजिलिएंस के बारे में

- यह आईस्पेस के हकुकुतो-आर मून मिशन 2 का हिस्सा है। इसमें टेनेशियस (TENACIOUS) माइक्रो रोवर भी शामिल है।
- इसके कमर्शियल कस्टमर पेलोड में वाटर इलेक्ट्रोलाइजर उपकरण, डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब आदि शामिल हैं।



### मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर

एक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (STR) में एक मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर का अवैध शिकार किया गया।

गौरतलब है कि दुनिया में केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में

- इन्हें 'ब्लैक टाइगर' भी कहा जाता है। हालांकि, यह बाघ की कोई अलग उप-प्रजाति नहीं है।
- ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेस क्यू (TAQPEP) जीन में एकल उत्परिवर्तन की वजह से ऐसे बाघों के शरीर पर अधिक काले रंग की या मोटी धारियां होती हैं।
- उन्हें 'स्पूडो-मेलानिस्टिक' भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर की सभी धारियां पूरी तरह से काली नहीं होती हैं।
- मेलानिज्म की मुख्य वजह मेलेनिन के उत्पादन में वृद्धि है।
  - ⊕ मेलेनिन, मेलानोसाइट्स कोशिका द्वारा उत्पादित होता है। यह बालों, त्वचा और आईरिस का रंग निर्धारित करता है।



### बाँडी मास इंडेक्स (BMI)

डापबिटीज फाउंडेशन इंडिया के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने 15 साल बाद भारत की "ओबेसिटी गाइडलाइंस" को अपडेट किया। इसमें "अधिक वजन (Overweight)" की जगह 'ओबेसिटी (मोटापा)-ग्रेड I' और 'ओबेसिटी (मोटापा)-ग्रेड-II' श्रेणियों को शामिल किया गया है।

- 2009 की गाइडलाइंस पूरी तरह से BMI मानदंड पर आधारित थी।

बाँडी मास इंडेक्स (BMI) के बारे में

- यह एक प्रकार का सांख्यिकीय सूचकांक है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसकी लंबाई के अनुसार उसके वजन की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- किसी व्यक्ति के वजन (किलोग्राम में) को उसकी लंबाई (वर्ग मीटर में) से विभाजित करके इसकी गणना की जाती है।
- इंडेक्स की कमियां:
  - ⊕ शारीरिक बनावट में अंतर के बावजूद लैंगिक आधार पर 'लीन बाँडी मास' (वसा रहित) और 'फैट मास' के बीच अंतर नहीं करता है।
    - ◆ पुरुषों में सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक 'लीन बाँडी मास' और कम 'फैट मास' होता है।
  - ⊕ यह शरीर में वसा के वितरण को नहीं मापता है।



### भारत रणभूमि दर्शन

रक्षा मंत्रालय ने अपनी 'रणक्षेत्र पर्यटन' (Battlefield Tourism) योजना के तहत 'भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप' लॉन्च किए हैं।

- यह वेबसाइट और ऐप रण-क्षेत्रों की यात्राओं के लिए सूचना प्राप्त करने एवं मंजूरी देने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेंगे। रण क्षेत्रों की यात्राओं में वर्चुअल टूर और ऐतिहासिक गाथाएं शामिल होंगी।
- भारतीय सेना ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ अन्य सीमा स्थलों को शॉर्टलिस्ट किया है, जहां अतीत में सैन्य कार्रवाई हुई है या युद्ध हुए हैं।
  - ⊕ इनमें अरुणाचल प्रदेश में किविथू और बुम ला दर्रा; लद्दाख में रेजांग-ला एवं पैगोंग त्सो, तथा डोकलाम (2017 संघर्ष का स्थल) शामिल हैं।

## सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



### तिरुवल्लुवर

15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया।

तिरुवल्लुवर के बारे में

- वे एक महान तमिल दार्शनिक, कवि और विचारक थे। ऐसा माना जाता है कि वे चेन्नई के मायलापुर में रहते थे।
- वे अपनी तमिल साहित्यिक कृति 'तिरुकुरल' के लिए जाने जाते हैं। इस ग्रंथ में नैतिकता, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रेम जैसे विषयों पर उनके दोहों का संग्रह है।
- ⊕ तिरुकुरल तीन प्रमुख अध्यायों के अंतर्गत वर्गीकृत है: आराम (धार्मिकता), पोरुल (धन), इन्बाम या कामम (आनंद या प्रेम)।
- तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का निर्माण भारतीय मूर्तिकार वी. गणपति स्थपति ने कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में किया था।
- भारत के प्रथम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन जल्द ही सिंगापुर में किया जाएगा।
- मूल्य: धार्मिकता, करुणा और न्याय।

